

आईआईटी निर्माण की आखिरी बाधा भी दूर

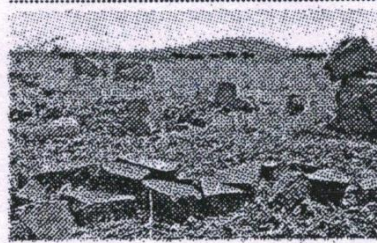
कैबिनेट ने जमीन ट्रांसफर पर स्टाम्प शुल्क
और पंजीयन फीस में दी छूट

भास्कर संवाददाता | इंदौर

फैक्ट फाइल

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी) इंदौर के निर्माण काम शुरू होने की अंतिम बाधा भी गुरुवार को राज्य सरकार ने दूर कर दी। भोपाल में हुई कैबिनेट बैठक में मंत्रीपरिषद ने निर्णय लिया कि आईआईटी परिसर के बीच में आ रही किसानों की 16.31 हेक्टेयर (40 एकड़) जमीन लेकर उन्हें अन्यत्र जमीन देने में स्टाम्प ड्यूटी व पंजीयन फीस से छूट दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि आईआईटी को सिमरोल ग्राम में मिली 501.6 एकड़ जमीन के बीच करीब 40 एकड़ जमीन के शासन के पास ट्रांसफर होने का मुद्दा अटका हुआ था। वन विभाग से क्लियरेंस मिलने पर 40 एकड़ की जमीन का मामला सुलझने के बाद आईआईटी इंदौर प्रबंधन जल्द निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। उधर संभागायुक्त प्रभात पाराशर आईआईटी जमीन दौरे के बाद प्रशासन को सात दिन के भीतर जमीन का सीमांकन कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दे चुके हैं।

प्रवेश द्वार से मुख्य मार्ग तक बनेगी सड़क- सिमरोल परिसर



- » आईआईटी की कुल लागत 2000 करोड़ रुपए।
- » प्रथम चरण में 760 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
- » इस राशि में 388 करोड़ रुपए निर्माण काम पर खर्च होंगे।
- » तीन साल में बनकर तैयार होगा आईआईटी का स्थायी भवन।
- » अभी आईआईटी में तीन कोर्स हैं। कुल 120 छात्रों को हर साल प्रवेश मिलता है।

और मुख्य मार्ग के बीच 300 मीटर से अधिक की दूरी है। आईआईटी इंदौर जल्द ही आईआईटी के प्रस्तावित दोनों प्रवेश मार्ग (द्वार एक व दो) से मुख्य मार्ग तक की करीब सौ-सौ फिट चौड़ी सड़क बनाएगा।